भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4146

उत्तर देने की तारीख 27 मार्च, 2023 (सोमवार)

6 चैत्र, 1945 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी राज्यों का विकास

†4146. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुदर्शन भगत:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास हेतु क्या विभिन्न प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रयासों द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान देश के सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में द्रुत गति से विकास हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) भारत सरकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए स्कीम के डिजाइन के अनुसार अनुमोदित वित्तीय परिव्ययों के भीतर विभिन्न फ्लैगशिप और अन्य स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार 55 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अवसंरचना विकास सहित क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करना अनिवार्य है। 10% जीबीएस के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से इन केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों द्वारा 3.01 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण (करोड़ रु. में)			
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2017-18	43,245	40,972	39,753
2018-19	47,995	47,088	46,055
2019-20	59,370	53,374	48,534
2020-21	60,112	51,271	48,564
2021-22	68,020	68,440	70,874
2022-23	76,040	72,540	47,785*
कुल	**3,54,782**	**3,33,685**	**3,01,565**
स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट का विवरण-11. **नोट:** वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय की जांच के अधीन हैं। * चालू वर्ष 2022-23 के लिए तीसरी तिमाही के अंत यानी 31.12.2022 तक सभी 55 मंत्रालयों/विभागों का कुल जीबीएस व्यय।			

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः-

• **<u>सड़क कनेक्टिविटी:</u>**

पिछले 03 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 60,093 करोड़ रुपये की राशि के कुल 4,686 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही प्रमुख राजधानी सड़क संपर्क परियोजनाओं में नागालैंड में दीमापुर-कोहिमा रोड (77.87 किमी) को 4 लेन का बनाना; अरुणाचल प्रदेश में नगांव बाईपास को होलोंगी (167 किमी) तक 4 लेन का बनाना; सिक्किम में बागराकोट से पाकयोंग (एनएच-717ए) (152 किमी) तक वैकल्पिक दो लेन राजमार्ग; मिजोरम में आइजोल-तुईपांग राष्ट्रीय राजमार्ग-54 (351 किमी) को 2 लेन का बनाना; मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 (20 किमी) के इम्फाल-मोरेह खंड को 4 लेन का बनाना और 75.4 किमी को 2 लेन का बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) के अंतर्गत 3,372.58 करोड़ रुपए की 77 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

• **<u>रेल कनेक्टिविटी:</u>**

पिछले तीन वर्षों के दौरान 77,930 करोड़ रुपये की लागत से 1,909 किमी की कुल लंबाई को कवर करते हुए पूरी तरह से/आंशिक रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाली 19 रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं और वे आयोजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 409

किलोमीटर लंबाई चालू कर दी गई है और मार्च 2022 तक 30,312 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

• **<u>वायु कनेक्टिविटी:</u>**

नागर विमानन मंत्रालय ने देश में सेवा रहित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से देश भर में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और हवाई यात्रा को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए 21.10.2016 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ान के तहत रूपसी, तेजू, तेजपुर, पासीघाट, जोरहाट, लीलाबाड़ी, शिलांग, पाक्योंग, ईटानगर और दीमापुर में हवाई अड्डों को शामिल करते हुए 64 रूट्स को प्रचालित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2014 में 9 हवाई अड्डे प्रचालनरत थे। वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16 प्रचालनरत हवाई अड्डे हैं। इसके अतिरिक्त, जीरो में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को भी चालू किया गया है।

- **<u>जलमार्ग कनेक्टिविटी:</u>**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,040.71 करोड़ रुपये की लागत से 4 जलमार्ग परियोजनाओं/कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**परियोजना / कार्य**	**लागत (करोड़ रुपए में)**
1	एन.डब्ल्यू.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) का व्यापक विकास	474
2	एन.डब्ल्यू.-16 (बराक नदी) का व्यापक विकास	148
3	पांडु (गुवाहाटी) में जहाज मरम्मत सुविधा का निर्माण और पांडु बंदरगाह (ब्रह्मपुत्र नदी) के लिए वैकल्पिक सड़क संपर्क का विकास	388
4	मिजोरम के लुंगलेई जिले में ख्वाथलंगतुईपुई - तुइचावंग नदी पर आईडब्ल्यूटी का विकास	6.18
5	त्रिपुरा में गुमटी नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास	24.53
	कुल	**1,040.71**

• **दूरसंचार कनेक्टिविटी:**

दूरसंचार विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। परियोजनाएं इस प्रकार हैं: (i) अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिले परियोजना: परियोजना लागत 1,255.59 करोड़ रुपये है, (ii) मेघालय परियोजना: (iii) कुल 1,358 टावर चालू किए गए हैं, (iv) भारतनेट परियोजना को देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड

कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, (v) भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारतनेट का उपयोग करते हुए देश भर के ग्राम पंचायतों/गांवों (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) में 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शनों को शुरू करने के लिए बीएसएनएल द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 14-03-2023 तक देश भर में प्रायोगिक परियोजना के तहत कुल 2,04,170 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, और (vi) 4 जी संतृप्ति परियोजना: इस परियोजना के तहत देश भर में 24,680 अनकवर्ड गांवों को 4 जी सेवाओं के साथ कवर करने का प्रस्ताव है। इसमें 6,279 गांवों में मौजूदा 2जी/3जी स्थलों का 4जी सेवा में उन्नयन भी शामिल है। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5,665 गांव शामिल हैं।

<u>विद्युत क्षेत्र</u>

विद्युत मंत्रालय ने भी पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2014 से विद्युत उत्पादन (जल/थर्मल) परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, पारेषण और वितरण नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 740 मेगावाट की 03 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) शुरू की गई हैं। मैसर्स असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा असम राज्य में 69.755 मेगावाट क्षमता (7x9.965 मेगावाट) की गैस आधारित विद्युत परियोजना नामतः लखवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना दिनांक 14.02.2018 को चालू की गई थी। इसके अतिरिक्त, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) दो प्रमुख अंतर-राज्य विद्युत पारेषण और वितरण स्कीमें नामतः (i) 6,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों (33केवी और उससे अधिक) के सुदृढ़ीकरण के लिए छह राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड) के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी); और (ii) 9,129.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास (एनईएसआईडी) स्कीम के तहत 273.01 करोड़ रुपये की 06 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) में 578.54 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों से संबंधित युवाओं के बीच आपसी संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के तहत 'युवा संगम' पहल की है।

*****